Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 10-03-2006

Participants : Pandey Dr. Laxminarayan

an>

Title : Need to set up a Horticulture University at Mandsaur, Madhya Pradesh.

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, कृषि देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। देश में बढती हुयी जनसंख्या, कृषि पर बढते हुए भारत तथा उपलब्ध कृषि भूमि में अधिकाधिक उत्पादन हो तथा विभिन्न प्रकार की फसलों को प्राप्त किया जाकर देश की आवश्यकता को पूरा किया जा सके, इस दृटि से कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जहां नित नये अनुसंधान किये जा रहे हैं तथा उसका लाभ भी कतिपय क्षेत्रों में प्राप्त हो रहा है। किंतु, इस प्रकार का लाभ सभी प्रदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों में नीचे स्तर तक मिले, इस हेतु जहां कृषि अनुसंधान क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय की आवश्यकता है वहीं देश के उद्यानिकी क्षेत्र के विस्तार की दृटि से भी काफी प्रयत्न किया जाना आवश्यक है।देश में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के साथ नकद फसलों का भी बहुतायत से उत्पादन किया जा रहा है जिसमें औधीय पादप, मिर्च, मसाले, सब्जियां और फल आदि सम्मिलित है किंतु उद्यानिकी क्षेत्र में विस्तार की दृटि से देश में केवल एकमात्र उद्यानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। मध्य प्रदेश उद्यानिकी क्षेत्र में जलवायु की दृटि अत्यंत उपयुक्त स्थान है किंतु यहां भी केवल एक ही कृषि महाविद्यालय है जो अपनीसम्पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहा है तथा अपने स्नातकों द्वारा इस लाभ पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश में उक्त संबध में उपयुक्तता की दृटि से वहां उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने के अनुकूल आधारभूत संरचनाएं हैं और उसमें भी मालवा अंचल का मंदसौर सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है।

अतः मेरा अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में स्थित मंदसौर में कृषि उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के बारे में आवश्यक निर्देश प्रदान करें ताकि आधारभूत संरचनाओं तथा उपयुक्त जल वायु का लाभ उठाकर विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदेश और आसपास के प्रदेशों में उद्यानिकी को और अधिक पर्याप्त महत्व देते हुए किसानों को तैयार किया जा सके और देश को उद्यानिकी उत्पादन और आर्थिक सम्पन्नता की ओर ले जाया जा सके। मेरा कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कट करें।

(iii) **Need to check fake advertisements inviting applications for employment with a view to prevent exploitation of unemployed youth in the country**